

## अनुसूचति जनजात (ST) सूची में संशोधन हेतु वधियक

### प्रलमिस के लयि:

राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग, अनुसूचति जनजात, संवधान की पाँचवी अनुसूची, संवधान की छठी अनुसूची ।

### मेन्स के लयि:

अनुसूचति जनजातियों की सूची में शामिल करने की प्रक्रया, भारत में जनजातियों से संबंधति संवधानिक प्रावधान और पहल ।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में 4 राज्यों - तमलिनाडु, कर्नाटक, हमिचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में [अनुसूचति जनजात \(ST\) सूची](#) को संशोधति करने की मांग करने वाले चार वधियकों को [संवधान \(ST\) आदेश, 1950](#) में प्रस्तावति संशोधनों के माध्यम से [लोकसभा](#) में पेश कयि गया था ।

## प्रस्तावति परिवर्तन:

- वधियक का उद्देश्य:
  - तमलिनाडु की ST सूची में [नारीकोरवन और कुरुवकिकरन पहाड़ी जनजातियों](#) को शामिल करना ।
    - [लोकसमति \(1965\)](#) ने भी अपनी रिपोर्ट में उन्हें सूची में शामिल करने की सफिरशि की थी ।
  - कर्नाटक की ST सूची में पहले से ही वर्गीकृत [काडू कुरुबा](#) के परयाय के रूप में [बेटटा-कुरुबा](#) को शामिल करना ।
  - छत्तीसगढ़ की ST सूची में पहले से वर्गीकृत भारया भूमया जनजात के लयि देवनागरी लिपि में अन्य समानार्थक शब्द जोड़ना ।
    - जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, वे सभी एक ही जनजात का हसिसा हैं, लेकिन उन्हें सूची से बाहर रखा गया था क्योंकि उनके नाम अलग-अलग हैं ।
  - सरिमोर ज़िले में ट्रांस-गरि क्षेत्र के [हट्टी समुदाय](#) को हमिचल प्रदेश की ST सूची में शामिल करना (लगभग पाँच दशकों के बाद) ।

## ST सूची में शामिल करने की प्रक्रया:

- राज्य द्वारा सफिरशि:
  - जनजातियों को ST की सूची में शामिल करने की प्रक्रया संबंधति राज्य सरकारों की सफिरशि से शुरू होती है, जसि बाद में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और अनुमोदन के लयि [भारत के महापंजीयक](#) को इसे प्रेषति करता है ।
- NCST से मंजूरी: इसके बाद सूची को अंतिम नरिणय के लयि कैबनेट को भेजे जाने से पहले [राष्ट्रीय अनुसूचति जनजात आयोग \(National Commission for Scheduled Tribes- NCST\)](#) द्वारा मंजूरी दी जाती है ।
- राष्ट्रपति की सहमति: अंतिम नरिणय करने की शक्ति राष्ट्रपति में नहिति है ([अनुच्छेद 342](#) के तहत) ।
  - अनुसूचति जनजात में [कसि भी समुदाय को शामिल करने की प्रक्रया संवधान \(अनुसूचति जनजात\) आदेश, 1950](#) में संशोधन करने वाले वधियक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही प्रभावी होती है ।

## भारत में अनुसूचति जनजातियों से संबंधति प्रावधान

- परभाषा:
  - भारत का संवधान अनुसूचति जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परभाषति नहीं करता है । [वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार](#), अनुसूचति जनजातियों को "बहषिकृत" और "आशकि रूप से बहषिकृत" कषेत्रों में रहने वाली "पछिड़ी जनजातियों" के रूप में मान्यता जाना जाता है ।
  - भारत सरकार अधनियम 1935 ने पहली बार प्रांतीय वधिनसभाओं में "पछिड़ी जनजातियों" के प्रतनिधियों को शामिल कयि जाने की मांग की ।
- संवधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 366 (25):** इसमें अनुसूचित जनजातियों को "ऐसी आदवासी जातिया आदवासी समुदाय या इन आदवासी जातियों और आदवासी समुदायों के भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिये **अनुच्छेद 342** में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है" परभाषित किया है।
- **अनुच्छेद 342(1):** राष्ट्रपति किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में (राज्य के मामले में **राज्यपाल** के परामर्श के बाद) उस **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जनजातियों/जनजातीय समुदायों/जनजातियों/जनजातीय समुदायों के कुछ भागों या समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में वनिरिदषित कर सकता है।**
- **पाँचवी अनुसूची:** यह **6वी अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान** नरिधारित करती है।
- **छठी अनुसूची:** असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम में **जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।**
- **वैधानिक प्रावधान:**
  - असपृश्यता के वरिद्ध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
  - **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989**
  - **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक वसितार) अधिनियम (पेसा), 1996**
  - **अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006।**

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

**[[[?]]]:**

प्र. यदकिसि वशिषित क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो नमिनलखित कथनों में कौन-सा एक कथन इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? (2022)

- इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर-जनजातीय लोगों के अंतरित करने पर रोक लगेगी।
- इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा।
- इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा।
- जसि राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे, उसे वशिष कोटिका राज्य घोषित किया जाएगा क्षेत्रों वाले राज्य को वशिष श्रेणी का राज्य घोषित किया जाएगा।

उत्तर: (a)

प्र. भारत के संविधान की कसि अनुसूची के तहत खनन के लिये नजि पार्टियों को आदवासी भूमिके हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019)

- तीसरी अनुसूची
- पाँचवी अनुसूची
- नौवी अनुसूची
- बारहवी अनुसूची

उत्तर: (B)

**[[[?]]]:**

प्र. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रतभेदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख वधिक पहलें क्या हैं? (2017)

**स्रोत: द हट्टि**